



Amrapali Village Residents Welfare Association

Amrapali Village, Gyan Khand-II, Kaala Patthar, Indirapuram

Ghaziabad-201014 (U.P.) # Registration Number: I-52637 / 2009

Email: avrwagzb@gmail.com # www.avrwa.com # www.facebook.com/avrwa

संदर्भ सं. : ए.वी.आर.डब्लू.ए./2016-17/ एल 2

दिनांक 11 जून, 2016

सेवा में,

श्री मान उपाध्यक्ष महोदय
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
विकास पथ, गाजियाबाद

विषय : काला पत्थर, इंदिरापुरम, (गाजियाबाद) के पास अवैध कूड़ा डंपिंग यार्ड को तत्काल प्रभाव से बंद करवाने के सम्बन्ध में।

महाशय,

इस पत्र के माध्यम से मैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का ध्यान इंदिरापुरम के काला पत्थर के पास नेशनल हाइवे-24 और हमारे आमपाली विलेज आवासीय सोसाइटी के बगल में अवैध कूड़ा डंपिंग यार्ड की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जिसके बारे में मेरे तथा अन्य स्थानीय निवासियों के द्वारा समय समय पर महोदय को पत्र तथा मौखिक रूप से अवगत कराया गया है।

हालांकि इस समस्या के बारे में तो विभाग के पास पुरी जानकारी उपलब्ध है, परंतु फिर भी बताते चलूँ कि डंपिंग यार्ड की वजह से पूरा इलाका दुर्गन्धमय रहता है और लोगों में सांस की बीमारी फैल रही है। कूड़ा डंपिंग यार्ड की स्थिति जस की तस बनी हुई है। पिछले वर्ष भी इस डंपिंग यार्ड की वजह से डेंगू फैल गया था जिसकी जानकारी जिले के आला अधिकारी को दी गयी थी तथा प्रिंट मीडिया में भी इसकी खबर आई थी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के अन्य आला अधिकारियों व मुख्य चिकित्सासे भी अनुरोध किया गया परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गयी। यहाँ विगत कई महीनों से कूड़ों को जलाया भी जाता है जिसकी जानकारी भी माननीय अधिकारीयों को दिया गया है। बारिश का मौसम आने वाला है, डर है कि अगर इस समस्या पर जल्द से जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में ये महामारी का रूप ले सकती है।

इस सम्बन्ध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में अनेको बार पत्राचार किया गया (पृष्ठ 3 से 6) लेकिन उसका आज तक ठोस जवाब नहीं आया। हालांकि विभाग ने ऑनलाइन जवाब में यह माना है कि प्रकरण भूमि जिसमें डंप यार्ड है उसका कुछ भाग जी डी ए के द्वारा अधिग्रहित है और उसे हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। ऑनलाइन शिकायत संख्या GDA3607 से इस बात की पुष्टि की जा सकती है (पृष्ठ 7)। इस सम्बन्ध में स्थानीय निवासियों ने अनेको बार जी.डी.ए. के उपाध्यक्ष व अन्य अधिकारीयों से मुलाकात की परन्तु आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। विगत 1 जनवरी 2016 को फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ऑनर्स एसोशियेशन, गाजियाबाद के प्रतिनिधि ने उपाध्यक्ष महोदय से मुलाकात करके समस्या से अवगत कराया और इस बारे में पत्र भी सौंप (पृष्ठ 8 से 10) तथा उपाध्यक्ष महोदय ने आश्वासन भी दिय परंतु पुन कोई कार्रवाई नहीं की गयी। बहुत सारे शिक्यत तो जी डी ए के हेल्पलाइन पर बिना कर्यवही के पडे हुए हैं।

इस संदर्भ में हमने गाजियाबाद नगर निगम (पृष्ठ 11 से 13), जिलाधिकारी महोदय से लेकर भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय व पर्यावरण मंत्रालय तक मैं शिक्यत की गयी परंतु शायद शिक्यत पत्र को कुछ तवज्जो नहीं दिय गया। जहाँ पर्यावरण मंत्रालय ने उसे रज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड को अग्रसरित किया (पृष्ठ 14 से 15), शहरी विकास मंत्रालय ने भी उत्तर प्रदेश शासन को अग्रसरित करके अपना किनार कर लिया (पृष्ठ 16)। प्रधानमंत्री कर्यालय ने भी इस सम्बन्ध में तीन बार प्रदेश के मुख्य सचिव को आवश्यक कर्यवही के लिये अग्रेषित किया (पृष्ठ 17 से 22), परन्तु किसी भी तरफ से इस समस्या का निवारण होते नहीं दिख रहा है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश से लेकर माननीय मुख्यमंत्री

रमेश कुमार



Amrapali Village Residents Welfare Association

Amrapali Village, Gyan Khand-II, Kaala Patthar, Indirapuram

Ghaziabad-201014 (U.P.) # Registration Number: I-52637 / 2009

Email: avrwagzb@gmail.com # www.avrwa.com # www.facebook.com/avrwa

महोदय को भी पत्र के द्वारा अवगत कराया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मेरे शिकायत पत्र को प्रधान सचिव, शहरी विकास मंत्रालय को कार्यवाही हेतु भेज दिया (पृष्ठ 23 से 27)। परंतु दुखद पहलु ये है कि अभी तक मामला के ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ है व समस्या जस का तस बना हुआ है। आपने अनेकों बार हमें भरोसा दिलाया लेकिन वह भी व्यर्थ ही साबित होता दिखाई दे रहा है। जन सुनवाई (तहसील दिवस) विभाग में भी दिनांक 8 फरवरी 2016 को आवेदन डाला गया जिसे जिलाधिकारी महोदय ने जी.डी.ए. के उपाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित किया। वेबसाइट पर स्थिति देखने पर पता चलता है कि अभी भी यह प्राधिकरण में ही लम्बित है (पृष्ठ 28)। इसके अलावे अनेकों बार अखबार और न्यूज़ चैनल पर भी इसके बारे में खबर आयी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। (पृष्ठ 29 से 36) विभाग के अधिकारी समय समय पर मीडिया में बयान देकर कार्रवाई का आश्वासन भर ही देते हैं।

महोदय, हमलोग भी इस राज्य के नागरिक हैं तथा हमें भी जीने के लिये प्रदूषणमुक्त वातावरण चाहिये। अतः आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस अवैध कूड़ा डंपिंग यार्ड से यथाशीघ्र मुक्ति दिलाने का मार्ग प्रस्तुत करें। हम जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। यदि यहां से डंपिंग यार्ड हटाया नहीं गया तो भविष्य में होने वाली बिमारी या जान माल के नुकसान की जिम्मेवारी विभाग पर ही होगी।

भवदीय,
राकेश कुमार

(राकेश कुमार)

सचिव, आमपाली विलेज रेसिडेंसियल वेलफेयर एसोसियेशन,
के-601, आमपाली विलेज, इंदिरापुरम
गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)

संलग्नक:

1. जी डी ए में किये गये पत्राचार की प्रति। (पृष्ठ 3 से 6)
2. जी डी ए द्वारा ऑनलाइन शिकायत संख्या GDA3607 के निष्पादन की प्रति (पृष्ठ 7)
3. फेडरेशन ओफ अपार्टमेंट ऑनर्स एसोशियेशन, गाजियाबाद के द्वारा दिया गया पत्र की प्रति। (पृष्ठ 8 से 10)
4. गाजियाबाद नगर निगम को भेजे गये पत्र की प्रति। (पृष्ठ 11 से 13)
5. पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अग्रसारित का प्रमाण। (पृष्ठ 14 से 15)
6. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को अग्रसारित होने का प्रमाण। (पृष्ठ 16)
7. प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को तीन परिवेदना पत्र अग्रसारित का प्रमाण। (पृष्ठ 17 से 22)
8. मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे गये पत्र व प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग को अग्रसारित प्रति। (पृष्ठ 23 से 27)
9. जन सुनवाई, उत्तर प्रदेश शासन को दिये गये परिवेदना और उसकी स्थिति। (पृष्ठ 28)
10. प्रिंट मीडिया में इस सम्बंध में छपे समाचार की प्रति। (पृष्ठ 29 से 36)

प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. प्रधान सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. मुख्यमंत्री कार्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
4. प्रेसीडेंट, फेडरेशन ओफ अपार्टमेंट ऑनर्स एसोशियेशन, गाजियाबाद।

जन सम्पर्क कार्यालय

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
पत्र प्राप्ति का विवर